समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

मोदी की डिग्री रहेगी निजी ; अमेरिका बेचैन — वैश्विक राजनीति और पारदर्शिता पर उठा बड़ा सवाल

Publisher

Published on 26 Aug 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर वर्षों से उठते सवालों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और यह पूरी तरह से उनकी निजी जानकारी के दायरे में आती है। इस फैसले ने एक बार फिर **निजता बनाम पारदर्शिता** की बहस को हवा दे दी है।

विपक्ष लगातार यह मांग करता रहा है कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद संभालते हैं, इसलिए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर कोई रहस्य नहीं रहना चाहिए। वहीं मोदी समर्थक तर्क देते हैं कि व्यक्ति की डिग्री या निजी शिक्षा का उसके कार्य प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता से कोई सीधा संबंध नहीं है।

राजनीतिक हलचल तेज

इस फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक न होना, लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यदि सब कुछ साफ-सुथरा है, तो डिग्री को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है?

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की निजता की रक्षा करते हुए सही निर्णय लिया है। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए उठाया जा रहा है और जनता वास्तविक मुद्दों से भटक रही है।

कानूनी पहलू: निजता का अधिकार बनाम सूचना का अधिकार

यह मामला सीधा-सीधा **Right to Privacy** और **Right to Information (RTI)** के टकराव का है।

- सूचना के अधिकार कानून (2005) का उद्देश्य नागरिकों को शासन में पारदर्शिता दिलाना है।
- वहीं, निजता का अधिकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता पा चुका है।

अदालत ने माना कि प्रधानमंत्री की डिग्री निजी जानकारी है और इसे सार्वजनिक करना उनके निजता अधिकार का उल्लंघन होगा। हालांकि इस फैसले ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं की शिक्षा और व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह निजी मानना सही है या नहीं।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य : अमेरिका क्यों बेचैन ?

इस पूरे घटनाक्रम के समानांतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल देखने को मिली। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका चीन की आर्कटिक रणनीति को लेकर बेचैन है।

- चीन ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए हैं।
- अमेरिका को आशंका है कि आर्कटिक में चीन का बढ़ता दखल न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए चुनौती बनेगा, बल्कि भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन को भी बदल सकता है।

इस संदर्भ में भारत का रुख भी अहम माना जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर चीन की इस बढ़ती सक्रियता का जवाब दे। यही कारण है कि भारत से जुड़े हर राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय पर अमेरिका की गहरी नजर है।

मोदी की डिग्री और वैश्विक छवि

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मामला घरेलू राजनीति का विषय भले हो, लेकिन इसका असर अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी पड़ सकता है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की शिक्षा और पृष्ठभूमि सार्वजनिक होती है। ऐसे में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री को निजी रखना उचित है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल राजनीतिक हथियार भर है और इसका शासन या विदेश नीति से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को "पारदर्शिता बनाम गोपनीयता" की लड़ाई बनाकर जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहा है।

विपक्ष की रणनीति और 2029 का चुनाव

राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विपक्ष 2029 के आम चुनाव तक इस मुद्दे को जीवित रखना चाहता है। विपक्षी पार्टियां इसे जनता के बीच "सच्चाई छुपाने" का मामला बताकर प्रचारित कर सकती हैं। वहीं भाजपा इसे "गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का मुद्दा बनाकर पेश कर सकती है।

अगर यह विवाद लंबे समय तक चलता है, तो यह निश्चित ही आने वाले चुनावी माहौल पर असर डाल सकता है।

जनता की राय बंटी हुई

सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस चल रही है।

- कुछ लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की शिक्षा पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए।
- वहीं कई लोग कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा मायने उनके काम और देश की प्रगति से है।

यह विभाजित राय बताती है कि लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाएं भी विविध होती हैं।

मोदी की डिग्री का विवाद महज़ शिक्षा का नहीं, बल्कि **लोकतांत्रिक पारदर्शिता, निजता के अधिकार और राजनीतिक रणनीति** का मिश्रण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसे कानूनी रूप से निजी घोषित कर दिया है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक बहस अभी खत्म होने वाली नहीं है।

वहीं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा भारत की विदेश नीति को और चुनौतीपूर्ण बना रही है। ऐसे में

भारत के प्रधानमंत्री की हर छोटी-बड़ी बात पर अंतरराष्ट्रीय निगाहें होना स्वाभाविक है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.